भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

शाही विकास मंत्रालय
अधिष्ठात्र

सं. १३८] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च २६, २००७/चैत्र ५, १९२९
No. १३८] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2007/CHAITRA 5, 1929

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली में रेल (दाबा आयुक्त का वेतन, पालन, सेवा के अन्य
निवेश और शर्तें नियम, २००७ है।

(२) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रस्तुत होगी।

2. परिभाषाएँ.—(१) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अर्थात न दर्शा हो,—

(क) "अधिनियम" दिल्ली में रेल (प्राधिकार और अनुसूचना) अधिनियम, २००२ (२००२ का ६०) अधिनियम है;

(ख) "दाबा आयुक्त" से अधिनियम को भारत ४५ के अधीन नियुक्त किया गया कोई दाबा आयुक्त अधिपत्त है;

(ग) "पालन" से अधिनियम की कोई धारा अधिपत्त है।

(२) उन अन्य सभी शब्दों और पदों को, जो हमें प्रयुक्त हैं, किसी परिभाषा नहीं हैं, वहीं अर्थ होगी जो उस अधिनियम में है।

3. वेतन और पालन.—(१) दाबा आयुक्त, ऐसे वेतन और पालन के लिए, जो किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अनुमोद

है, हमदर्द होगा :

परंतु किसी ऐसी व्यवस्था को, दाबा आयुक्त के रूप में नियुक्त को मामले में, जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में संबंधित हो चुका है और जो, पेंशन, उपराज, अधिश्रृंखला विभाग निधि में नियोजक अधिकार या संबंधित फायदों के अन्य प्रतिक द्वारा किसी संबंधित फायदे को प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, उसके तौर पर ही पेंशन, अधिश्रुति विभाग निधि में नियोजक अधिकार के के भारतीय संसद या संबंधित-फायदों के अन्य प्रतिक, या कोई दूसरे उसके द्वारा प्राप्त किए, 
राह या प्राप्त किए जाने हैं, की कुल रकम, परंतु यही होगी।

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यवस्था की, दाबा आयुक्त के रूप में नियुक्त को मामले में, जो भारतीय विधिक संबंधी कुशली के साथ । में
पद धारण करने के पर्याप्त संबंधित हो चुका हो या भारत सरकार के संबंधत सचिव से अन्यून वेतनमान को किसी नियोजित न्यायिक पद से
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

PART II—SEC. 3(0)

Ministry of Urban Development

Notification

New Delhi, the 19th March, 2007

G.S.R. 235(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of Sub-section (2) of Section 56 read with Section 51 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Metro Railway (Salary, Allowances, Other Terms and Conditions of Service of the Claims Commissioner) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) “Act” means the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002).

(b) “Claims Commissioner” means the Claims Commissioner appointed under Section 48 of the Act.

(c) “section” means a section of the Act;

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary and allowances.—(1) The Claims Commissioner shall be entitled to such pay and allowances as are admissible to a Judge of a High Court:

Provided that in case of appointment of a person as Claims Commissioner, who has retired as a Judge of a High Court and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits, by way of

...
pension, gratuity, employer’s contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of employer’s contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him:

Provided further that in the case of appointment of a person as Claims Commissioner, who has retired from service after holding a post in Grade 1 of Indian Legal Service, or has retired from a civil judicial post carrying scale of pay not less than that of a Joint Secretary to the Government of India after holding that post for at least three years, and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits, by way of pension, gratuity, employer’s contribution to Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension or pensionary equivalent of Employer’s Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Accommodation.—(1) The Claims Commissioner, if he is serving or a retired Judge of a High Court, shall be entitled to residential accommodation on terms as admissible to a serving Judge of a High Court.

(2) Where the Claims Commissioner is not provided with the accommodation referred to in sub-rule (1), he may be paid, every month, a House Rent Allowance at the rate of thirty per cent of his basic pay.

5. Facilities for medical treatment.—The Claims Commissioner shall be entitled to medical treatment and hospital facilities, applicable to the officer of equivalent pay scale, as provided in the Central Government Health Scheme.

6. Conditions of service, etc.—Notwithstanding anything contained in these rules, the conditions of service of and other facilities available to the Claims Commissioner shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court.

7. Office accommodation and other facilities.—The metro railway administration shall provide necessary office accommodation, staff, conveyance and other facilities and assistance to the Claims Commissioner for the discharge of his duties under the Act.

8. Residual provision.—Matters relating to the conditions of service of the Claims Commissioner with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Claims Commissioner.

9. Power to relax.—The Central Government may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax the provisions of any of these rules, in respect of any class or categories of persons.

S. K. LOHIA, Director (Urban Transport)
3. शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति.—(1) कंद्रीय सरकार, दावा आयुक्त पर कृप्या का प्राप्त करने के संबंध में
कदाचार या अपराधशास्त्र के किसी निरीक्षा आरोप अभिलेखित करते हुए, किसी शिकायत की प्राप्ति पर, ऐसी शिकायत को प्रारंभिक समीक्षा
करेगी।

(2) यदि, कंद्रीय सरकार, प्रारंभिक संविधा पर अभिलेख को जांच करना आवश्यक समझती है तो वह शिकायत में लिखे गए
अभिलेखों के आरोपों का अन्वेषण करने के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर कभी समिति के समय, उन समाचार कस्तो महिला
शिकायत रखेगी:—

(i) सचिव (समवस्थापन और लोक सचिवालय)
(ii) सचिव, राहती सचिवालय
(iii) सचिव, निरीक्षा नियम और उद्योग

3. समिति, अन्वेषण को अपनी प्रक्रिया और रीति प्रकाशित करेगी, जिसमें शिकायतकर्ताओं के साथ का अवलोकन और जांचे
से सुरू करके समीक्षा को संस्था भी समीक्षित है, जो इन निरीक्षियों के अन्य समस्या या ग्रस्तादि के व्याख्या द्वारा किया जा सकता है।

(4) समिति, अन्य निरीक्षयों को कृप्या को, यथायोग्य प्रश्न या अवधि के भीतर, जो इस निरीक्ष निरीक्ष द्वारा निरीक्षित
की जाए, प्रस्तुत करेगी।

4. न्यायाधीश द्वारा जांच किया जाना.—(1) पहले कंद्रीय सरकार की यह राय में दावा आयुक्त का कदाचार या अपराधशास्त्र के
किसी अभिलेखण की समस्या को जांच करने के लिए नियुक्तकरण आवश्यक है, तो भार भारत के घुसी या पृथ्वी को, जांच करने के लिए,
उच्चतम न्यायाधीश के किसी न्यायाधीश के न्यायाधीश स्तर करने के लिए उसमें प्राधिक्य करते हुए कई निरीक्षण करती है।

(2) कंद्रीय सरकार, जांच करने के प्रस्ताव के लिए, भारत के घुसी या पृथ्वी द्वारा न्यायाधीश नियुक्त किये गए उच्चतम
न्यायाधीश को (जिसे उसमें इसके अध्यक्ष न्यायाधीश कहा गया है), आदेश द्वारा निरीक्षण करती है।

(3) उस निरीक्ष (2) के अधीन किसी न्यायाधीश की निगमन को सुनवाई, दावा आयुक्त को की जाती है।

(4) कंद्रीय सरकार, न्यायाधीश को निम्नलिखित की एक प्रति अप्रतिक्रिया करती है।

(5) न्यायाधीश, ऐसे समय का और समय के भीतर, जो कंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षित किया जाए, जांच समाप्त करेगा।

(6) न्यायाधीश, ऐसे समय का और समय के भीतर, जो कंद्रीय सरकार द्वारा निरीक्षित किया जाए, प्रस्तुत करने का
न्यायाधीश अधिकार रखता है।

(7) जहाँ यह अभिलेखित किया गया है कि दावा आयुक्त किसी शारीरिक या लोकस्वरूप अपराधशास्त्र के कारण समाप्त अपराधी
अपराधी के लिए नियुक्त किया गया है, वह न्यायाधीश, ऐसे चिकित्सक व्यक्ति के द्वारा, जो कंद्रीय
सरकार द्वारा ऐसे प्रयोग के लिए नियुक्त किया गया है, दावा आयुक्त की चिकित्सक शरीर की लिए प्रबंधन कर सकता है।

(8) चिकित्सक व्यक्ति के द्वारा इसे शारीरिक रूप से जांच समाप्त करता है, जैसे अभिलेख कस्तो और न्यायाधीश को, यह कदाचार
है कि उस अभिलेख कस्तो जिसमें दावा आयुक्त पर पर बने रहने के लिए अपराध होता है, ऐसा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

(9) कंद्रीय सरकार, ऐसे चिकित्सक शरीर का प्रबंधन है जैसे निरीक्षित व्यक्ति के द्वारा, जिससे उस समय के
कदाचार के द्वारा दावा आयुक्त ने नियुक्त किया है, तथा अपराधी के रूप में दावा आयुक्त ने नियुक्त किया है, कदाचार
करते हुए, प्रस्तुत करें और न्यायवाची ऐसे रिपोर्ट के प्रबंधन का प्राप्ति पर उपभोग कर सकता है कि दावा आयुक्त ऐसे शारीरिक और नामिक
अभिलेख के रूप में, जैसे सचिवालय में अभिलेखित को गई है, द्वारा है।

(10) न्यायाधीश, दावा आयुक्त की निरीक्षित कदाचार और निरीक्षित रिपोर्ट, यदि कई हो, पर विचार करने के पश्चात उप-निरीक्ष
(4) के खंड के द्वारा निरीक्षित आरोपों को निरीक्षित का, जांच समाप्त और ऐसे समय में दावा आयुक्त के प्राप्ति का एक नया निरीक्ष निरीक्ष द्वारा निरीक्षित कदाचार पहले की जाए।
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

G.S.R. 236(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Sub-section (2) of Section 56 read with Sub-section (3) of Section 51 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely,—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Metro Railway (procedure for investigation of misbehaviour or incapacity of the Claims Commissioner) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) “Act” means the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002).

(b) “Claims Commissioner” means the Claims Commissioner appointed under Section 48 of the Act.

(c) “Section” means a section of the Act ;

(d) “Judge” means the Judge of the Supreme Court appointed for conducting the inquiry under sub-rule (1) of rule 3;

(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Committee for investigation of complaints.—(1) The Central Government, on receipt of a complaint alleging any definite charges of misbehaviour in respect of or incapacity to perform the functions of the office in respect of Claims Commissioner, shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the Central Government considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint :—

(i) Secretary (Coordination and Public Grievances) Cabinet Secretariat —Chairman

(ii) Secretary, Ministry of Urban Development —Member

(iii) Secretary, Department of Legal Affairs Ministry of Law and Justice —Member
(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the Central Government as early as possible within a period that may be specified by the Central Government in this behalf.

4. Judge to conduct inquiry.—(1) If Central Government is of the opinion that there are reasonable grounds for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehaviour or incapacity of Claims Commissioner, it shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The Central Government shall by order appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India (hereinafter referred to as Judge) for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Claims Commissioner.

(4) The Central Government shall forward to the Judge a copy of—

(a) the articles of charges against the Claims Commissioner concerned and the statement of imputation;

(b) the statement of witnesses, if any; and

(c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the Central Government.

(6) The Claims Commissioner concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Claims Commissioner is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the judge may arrange for the medical examination of the Claims Commissioner by such Medical Board as may be appointed for the purpose by Central Government and the Claims Commissioner concerned shall submit himself to such Medical Examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Claims Commissioner as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Claims Commissioner unfit to continue in office.

(9) If the Claims Commissioner refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Claims Commissioner has refused to undergo and the Judge may on receipt of such report presume that the Claims Commissioner suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Claims Commissioner and the Medical Report if any amend the charges referred to in clause (a) to sub-rule (4) and in such a case the Claims Commissioner shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or any advocate to present the case against the Claims Commissioner.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Claims Commissioner shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

5. Inquiry Report.—After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the Central Government stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charge separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

6. Provisions of Civil Procedure Code not binding.—The Judge, while conducting an inquiry under rule 4, shall not be bound by the procedure laid down by the Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of his enquiry.
7. **Suspension of Claims Commissioner.**—Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the Central Government keeping in view the gravity of charges may suspend the Claims Commissioner against whom a complaint is under investigation or inquiry.

8. **Subsistence allowance.**—The payment of subsistence allowance to Claims Commissioner under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay.

[F. No. K-14011/52/2003-MRTs/Metro]

S. K. LOHIA, Director (Urban Transport)

अधिसूचना

चौंदिल, 19 जून, 2007

स.कृ.न. 237(3),—केंद्रीय राजकीय हिल्ली मैदान रेल (प्रकाशन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 56 की मान-धारा (2) के अंत में (iii) और धारा 100 की उपधारा (2) के अंत में (a) के साथ विशिष्ट धारा 55 की उपधारा (3) और धारा 57 द्वारा प्रति घटनायें की प्रमाण करते हुए नियमानुसार नियम बनाये हैं, अतः

1. **संक्षिप्त नाम और प्रफेशन।**—(1) इन नियमों का उपयोग नाम हिल्ली मैदान रेल (रेल द्वारा आयुक्त द्वारा अपनाया गया वातावरण और पुर्त्रकटा) के कारण कार्य अपराधी है यूनिक और पुर्त्रकटा के कारण अपराधी श्रेणी के आदेशों में संदर्भ प्रतिक्रिया की रूपमें नियम 2007 है।

(2) ये राज्य में प्रकाशन की तारीख को प्रस्तुत होगी।

2. **परिभाषाएं।**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अस्पष्ट न हो,—

(२) "अधिनियम" द्वारा हिल्ली मैदान रेल (प्रकाशन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) अधिनियम है;

(३) "दाया आयुक्त" द्वारा अधिनियम की धारा 48 के अंधिर निदित दाया आयुक्त अधिनियम है;

(४) "पुर्त्रकटा" द्वारा अधिनियम अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) में करिता प्रकृति को है और जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु या अवधिक श्रेणी अंतर्निहित है;

(५) "आयुक्त" द्वारा अधिनियम की धारा 58 के अंधिर दाया आयुक्त का कोई आयुक्त करते आवेदन या व्यक्ति अधिनियम है;

(६) "प्रकरण" द्वारा इन नियमों में उपबोध कोई प्रकेष्ट्र अधिनियम है;

(७) "विधि व्यवसायी" के बिना अथवा जो अधिकारिक अधिनियम, 1961 (1961 का 21) की धारा 2 की उपधारा (२) के अधिन हैं;

(८) "विधि प्रतिनिधि" द्वारा कोई व्यक्ति अधिनियम है जो अधिकार की संधि का विधि प्रतिनिधि है;

(९) "अनुसूची" द्वारा इन नियमों में उपबोध कोई अनुसूची अधिनियम है;

(१०) "धारा" द्वारा अधिनियम की कोई दाया अधिनियम है;

(११) उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषाओं में नहीं है वहों अर्थ होगी जो उनके अधिनियम में हैं।

3. **आदेशों को प्रभावित करने लिए प्रक्रिया।**—(१) मैदान रेल को प्रणली के कार्यवाचन में है यूनिक तथा पुर्त्रकटा के कारण है यूनिक श्रेणी या पुर्त्रकटा की है जरूरत प्रति संदर्भ में प्रतिक्रिया के संदर्भ में लेकर आयुक्त उपबोध में दिए गए प्रति में आयुक्त द्वारा व्यवस्था रूप से प्रति संवृत्त व्यक्ति द्वारा देना।

(२) उपनियम (१) में निर्देश आयुक्त द्वारा आयुक्त को रजिस्ट्रेशन बाल्क द्वारा भी प्रस्तुत कराया।

(३) उपनियम (१) या उपनियम (२) के अंधिर आयुक्त दो प्रतिक्रिया में होगा।

(४) प्रवेश आयुक्त, अधिकारियों की रूप एक अर्थ द्वारा स्पेशल दायरा किया हुआ है।

4. **आयुक्त की संवृत्ताः**—(१) दाया आयुक्त या उसके द्वारा प्रति संवृत्त कर्मचारिवर प्रवेश आयुक्त पर दायरा दिवसों प्रति या प्रति दिन्नियम 3 के अंधिर व्यक्त द्वारा प्रयत्न हुआ है और पुष्टि किया गया है।

(२) यदि आयुक्त की संवृत्तार् करने पर क्रम में पाया जाता है तो वह रजिस्ट्रेशन बाल्क और उस प्रमेय संवृत्त देना।

(३) यदि आयुक्त की संवृत्तार् करने पर तृप्तिपूर्ण पाया जाता है और दोप है। प्रति संवृत्त का जा है, दाया आयुक्त उसे अपनी
8 THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]

(4) In the event of a dispute arising under the terms of the Agreement, the Arbitration Board may, in its discretion, submit such matters as may be referred to it, to a competent Government of India, for determination and such decision as may be so arrived at shall be final and binding on the parties.

(5) All disputes arising under the Agreement or in connection with the Agreement shall be determined in accordance with the provisions of the Agreement and the decision of the competent Government of India shall be final and binding on the parties.

5. M. J. N. Prasad to the Chairman.—(1) The Chairman is hereby authorized to call for the report of the Special Committee and to give such directions as may be necessary for ensuring that the report is submitted within the time limit specified in the Agreement.

(2) The Chairman may, for the purpose of receiving the report, request the Special Committee to submit a draft report for consideration at a meeting of the Committee.

6. The President of the Council.—(1) The President of the Council is hereby authorized to call for the report of the Special Committee and to give such directions as may be necessary for ensuring that the report is submitted within the time limit specified in the Agreement.

(2) The President may, for the purpose of receiving the report, request the Special Committee to submit a draft report for consideration at a meeting of the Council.

7. The Secretary of the Council.—(1) The Secretary of the Council is hereby authorized to call for the report of the Special Committee and to give such directions as may be necessary for ensuring that the report is submitted within the time limit specified in the Agreement.

(2) The Secretary may, for the purpose of receiving the report, request the Special Committee to submit a draft report for consideration at a meeting of the Council.

8. The President of the Council.—The President of the Council is hereby authorized to call for the report of the Special Committee and to give such directions as may be necessary for ensuring that the report is submitted within the time limit specified in the Agreement.

9. The Secretary of the Council.—The Secretary of the Council is hereby authorized to call for the report of the Special Committee and to give such directions as may be necessary for ensuring that the report is submitted within the time limit specified in the Agreement.

10. The President of the Council.—The President of the Council is hereby authorized to call for the report of the Special Committee and to give such directions as may be necessary for ensuring that the report is submitted within the time limit specified in the Agreement.

11. The Secretary of the Council.—The Secretary of the Council is hereby authorized to call for the report of the Special Committee and to give such directions as may be necessary for ensuring that the report is submitted within the time limit specified in the Agreement.
परन्तु यदि समान दुरंती के कारण हुई एक से अधिक शक्ति के लिए प्रतिक्रिया ऐसी अत्यधिक शक्ति के संबंध में संरेख होगा:
परन्तु यह और कि ऐसी सभी शक्तियों के संबंध में पूर्ण प्रतिक्रिया 80,000 रु. (अत्यधिक नहीं होगा)।
(4) यहाँ किसी शक्ति के लिए प्रतिक्रिया संरेख किया गया है जिससे कि वह शक्ति बनी है जिससे प्रतिक्रिया के माध्यम से संरेख भूमि है यदि शक्तिशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या शक्ति के अधीन पर उसके पश्चिम उसकी मृत्यु जाती है तो अतिरिक्त प्रतिक्रिया मृत्यु की लिए संरेख हृदय शक्ति या उसे तहले से दी गई रक्त के मध्य अंदर को समय तक संरेख होगा।
(5) यहाँ द्वारा उसके अधिकार समाप्त करने के कारण में से जाने वाले भाग की शक्ति, जन्म या शक्ति के लिए प्रतिक्रिया द्वारा आयुक्त द्वारा उस सूची तक संरेख होगा, जो स्वामी की सभी परिकल्पनाओं में चुकाई अनुरोधित करें।
20. प्रतिक्रिया की सीमा—नियम 19 में अर्थशास्त्रिक किसी व्यक्ति को होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन किसी एक व्यक्ति के संबंध में संरेख पूर्ण प्रतिक्रिया चार लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

अनुसूची
(नियम 19 देखें)
भाग 1
प्रतिक्रिया की रक्षा
(रूपये में)
यदू के लिए
4,00,000
भाग 2
1. दोनों गांवों को हानि या उत्तराधिकार संग्रहों पर बिंच्छन के लिए
4,00,000
2. एक गांव और एक शेखर का भाग के लिए
4,00,000
3. दोनों गांवों का कुल से दोहरा बिंच्छन, या एक गांव और शेखर से बिंच्छन और दूसरे गांव का भाग के लिए
4,00,000
4. दुक शासन के इस वस्त्र एक भाग के रूप में दूसरे ऐसा कोई काम करवाने में अधिक न हो जाता है यथावत लिए दुक शासन आवश्यक है, के लिए
4,00,000
5. चारों के प्रसारण गेंदरटा, के लिए
4,00,000
6. पूर्ण बिंच्छन, के लिए
4,00,000
भाग 3
1. बन्दों सन्धि से बिंच्छन के लिए
3,60,000
2. बन्दों से नीचे बिंच्छन, जब भी स्थानिक अंप्रिक्ष के सिरे से 8" निम्न हो, के लिए
3,20,000
3. अंप्रिक्ष के सिरे से 8" से क्षूरु से सिरे से नीचे 4-1/2" से नीचे बिंच्छन, के लिए
2,80,000
4. एक गांव को या एक गांव के अंग्रेज और दोनों अंग्रेजों को हानि, या जूर्स के लिए से 4-1/2" से नीचे बिंच्छन, के लिए
2,40,000
5. अंग्रेज की हानि के लिए
1,20,000
6. अंग्रेज की और उसकी कर्त्ता-अधिक की हानि के लिए
1,60,000
7. एक गांव का चार अंग्रेजों को हानि के लिए
2,00,000
8. एक गांव की तीन अंग्रेजों को हानि के लिए
1,20,000
9. एक गांव की दो अंग्रेजों को हानि के लिए
80,000
10. अंग्रेज की अधिक अंग्रेज-अधिक की हानि के लिए
80,000
11. दोनों पार्टी का बिंच्छन जिसके परिणामस्वरूप अंग्रेज मात्र रह जाए, के लिए
3,60,000
12. प्रपड़ा-अधिक सन्धि से दोनों पार्टी को बच अंग्रेजों की हानि के लिए
3,20,000
13. प्रपड़ा-अधिक सन्धि से दोनों पार्टी के बच अंग्रेजों की हानि के लिए
1,60,000
14. निकटस्थ अंग्रेज-अधिक सन्धि के निकट दोनों पार्टी को बच अंग्रेजों की हानि के लिए
1,20,000
15. निकटस्थ अंग्रेज-अधिक सन्धि के दूर दोनों पार्टी के बच अंग्रेजों की हानि के लिए
80,000
16. निकटस्थ पर बिंच्छन
3,60,000
17. निकटस्थ से नीचे बिंच्छन, जबकि स्थानिक कृत काने अवधि के प्रसन्न से सिरे नागर जाने पर 5" से अधिक लंबा न हो, किन्तु मध्यम से आगे न हो के लिए
3,20,000
<table>
<thead>
<tr>
<th>प्रतिकर की रकम (रुपये में)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>18. निरंतर से नीचे लिखित, जब कि स्थरण बूहत उठक अस्तित्व के सिरे से नापे जाने पर 2,80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>19. मण्डपकों के नीचे से पटनों को 3-1/2&quot; नीचे तक लिखित, जब कि स्थरण 3-1/2&quot; से अधिक हो, तथापि 2,40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>20. पटनों के नीचे लिखित, जब कि स्थरण 3-1/2&quot; से अधिक हो, तथापि 2,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td>21. अधिकतम सहित रकम का अनुपात 2,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td>22. पटनों से नीचे लिखित, जबकि स्थरण 3&quot; से अधिक न हो को लिए 1,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>23. एक नेत्र की हालि, जब कि कोई अन्य समस्या न हो और दूसरा नेत्र समान हो, को लिए 1,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>24. एक नेत्र का लिखित, जिसके परिणामस्वरूप अंततः मात्र रह जाए, को लिए 1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>25. प्रदानकित-अस्थिर सत्य से निकट के एक नेत्र का लिखित, को लिए 1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>26. अंधकार एहत रेङ्जियन अस्थिर 1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>27. एक नेत्र की दृष्टि की हालि, जब कि नेत्रलोक में समस्या या विद्रोह न हो और दूसरा नेत्र समान हो, को लिए 1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>28. प्रदानकित-अस्थिर सत्य से एक पर की सब अंथियाँ की हालि, को लिए 80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>29. निरंतर सत्य का अस्थिर 80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>30. बड़ी हदियों का अस्थिर—दोनों अंगों का फैसला 80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>31. बड़ी हदियों का अस्थिर—भों दोनों अंगों का हुम्मूर तंडूलक 60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>32. सत्य एहत श्रेणी का अस्थिर 40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>33. बड़ी हदियों का अस्थिर-एक अंग का फैसला टेबिल हो 40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>34. बड़ी हदियों का अस्थिर-एक अंग का हुम्मूर, तंडूलक और अल्पना 32,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

उपाधिक

प्राप्ति

(विभाग 3 देखें)

दिल्ली में डेली रेंट (अधिकार और अनुशंसा) अधिनियम, 2002 को से बाद 58 के अंतर्गत यात्रियों दो मूल में एवं को लिए जाने वाले पाण्ड को नद दी गई या अंश की वाणिज्य प्रतिकर के लिए दर्ज की गई, आवेदन।

मामलों का नाम:

भाग-1

भाग-2

क्रम सं.

संगणन दस्तावेजों का विवरण

पृष्ठ सं.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

आवेदक के हस्ताक्षर

दर्जास अनुसार से दर्ज के लिए

फाइल करने की तारीख

या

दर्ज के लिए प्राधिक की तारीख

रजिस्ट्रेशन सं.
NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2007

G.S.R.237 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of Sub-section (2) of Section 56 and clause (d) of Sub-section (2) of section 100 read with Sub-section (3) of Section 53 and Section 57 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Metro Railway (Procedure to be followed by the Claims Commissioner and amount of compensation payable in case of death and injuries due to accidents) Rules, 2007.
2. Definitions—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,
(a) “Act” means the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002);
(b) “Claims Commissioner” means the Claims Commissioner appointed under Section 48 of the Act;
(c) “accident” means a circumstance which is of the nature described in sub-section (1) of Section 38 of the Act and
which involves death or personal injury to passengers;
(d) “applicant” means a person making an application to the Claims Commissioner under Section 58 of the Act;
(e) “Form” means a form appended to these rules;
(f) “legal practitioner” shall have the same meaning assigned under Clause (i) of Section 2 of the Advocates
Act, 1961 (25 of 1961);
(g) “legal representative” means a person who in law represents the estate of the deceased;
(h) “Schedule” means a Schedule appended to these rules;
(i) “Section” means a Section of the Act.
(2) All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively
assigned to them in the Act.
3. Procedure for filing applications—(1) The application for payment of compensation in respect of accidents
involving death of, or bodily injury to person or damage to any property arising out of the working of the Metro Railway to
the Claims Commissioner shall be presented in the form given in the Annexure either by the applicant in person or by his duly
authorized person.
(2) An application referred to in sub-rule (1) may also be sent by registered post to Claims Commissioner.
(3) The application under sub-rule (1) or sub-rule (2) shall be presented in duplicate.
(4) Every application shall be typed legibly in double space on one side of paper of good quality.
4. Scrutiny of application—(1) The Claims Commissioner or the staff authorized by him shall endorse on every
application the date on which it is represented or received through post under rule 3 and sign the endorsement.
(2) If the application on scrutiny is found to be in order, it shall be registered and given a serial number.
(3) If the application on scrutiny is found to be defective and the defect noticed is formal in nature, the Claims
Commissioner may allow the applicant to rectify the same in his presence and if the defect is not formal in nature, the Claims
Commissioner or the staff authorized by him may allow the applicant such time to rectify the defect as he may deem fit.
(4) If the applicant fails to rectify the defect within the time allowed under sub-rule (3), the Claims Commissioner
may, by order and for reasons to be recorded in writing, decline to register the application and notify the applicant
accordingly.
(5) An appeal against the order passed under sub-rule (4) may be preferred by the person aggrieved within 15
days from the date of such order and such appeal shall be dealt with and disposed of by the Claims Commissioner whose
decision thereon shall be final.
5. Notice to Metro Railway Administration—(1) The Claims Commissioner shall issue notice to Metro Railway
Administration to show cause against the application on a date of hearing to be specified therein. Such notice shall be
accompanied by a copy of the application.
(2) If the representative of Metro Railway Administration does not appear on the date specified in the notice, or
appears and admits the claim, the Claims Commissioner shall forthwith proceed to dispose of the application.
(3) If the Metro Railway Administration contests the claim, it may file a reply along with copy of such document
on which it relies on or before the date of hearing and such reply and copies of the document shall form part of the record.
6. Filing of an Affidavit.—(1) The Claims Commissioner may direct the party to give evidence, if any, by affidavit.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) where the Claims Commissioner if considers necessary
for just decision of the case, he may order cross-examination of any deponent.
7. Filing of reply and other document by the respondents.—(1) Metro Railway Administration may file its reply to
the application and copies of the documents on or before the date of hearing of the application.
(2) In reply filed under sub-rule (1), the Metro Railway Administration shall specifically admit, deny or explain the
facts stated in the application and state additional facts necessary in its reply.
8. Summary disposal of application.—The Claims Commissioner may, after considering the application, summarily
dismiss the application, if for reasons to be recorded in writing, he is of the opinion that there are not sufficient grounds for
proceeding therewith.
9. Ex-parte hearing and disposal of application.—(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the applicant appears and the representative of Metro Railway Administration does not appear, the Claims Commissioner may, in his discretion adjourn the hearing or hear and decide the application ex-parte.

(2) Where an application has been heard ex-parte against the Metro Railway Administration, the latter may apply to the Claims Commissioner for an order to set aside it and if the Metro Railway Administration satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or that its representative was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the ex-parte hearing upon such terms as it thinks fit and shall appoint the day for proceeding with the application.

10. Disposal of application in default.—(1) Where on the date fixed for hearing the application or any other date to which such hearing may be adjourned, the representative of Metro Railway Administration appears and the applicant does not appear, the Claims Commissioner may, in his discretion adjourn the hearing or hear and decide the application in default.

(2) Where an application has been heard and disposed in default against the applicant, the latter may apply to the Claims Commissioner for any order to set aside it and if the applicant satisfies the Claims Commissioner that the notice was not duly served or he was prevented by any sufficient cause from appearing, the Claims Commissioner may make an order setting aside the dismissal in default, upon such terms as he thinks fit and shall appoint the day the proceeding with the application.

11. Powers of Claims Commissioner.—The Claims Commissioner shall have, for the purposes of discharging his functions under the Act, the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908, while trying a suit, in respect of the following matters, namely:

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
(b) requiring the discovery and production of documents;
(c) receiving evidence on affidavit;
(d) subject to the provisions of Sections 123 and 124 of the Indian Evidence Act, 1872, requisitioning and public record or document or copy of such record or document from any office;
(e) issuing commissions for the examination of witness or documents;
(f) reviewing his decisions;
(g) dismissing an application for default or ex-parte; and
(h) setting aside any order of dismissal of any application for default or any order passed by it ex-parte.

12. Summoning of witnesses and method of recording evidence.—(1) If an application is presented by any party to the proceedings for summoning of witnesses, the Claims Commissioner shall issue summons for the appearance of such witnesses unless the considers that their appearance is not necessary for the just decision of the case.

(2) The Claims Commissioner shall make a brief memorandum of substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds and such memorandum shall form part of the record:

Provided that if the Claims Commissioner does not make such memorandum, he shall record the reasons for his inability to do so and shall cause such memorandum to be made in writing from his dictation and shall sign the same, and such memorandum shall form part of the record.

13. Decision of the Claims Commissioner.—The Claims Commissioner shall decide every application as expeditiously as possible on perusal of documents, affidavits and other evidence, if any, and after hearing such oral argument as may be advanced.

14. Order to be passed and signed.—(1) The Claims Commissioner, after hearing the applicant and the Metro Railway Administration, shall pass an order as he thinks fit at once or, as soon as thereafter as may be practicable.

(2) Every order of the Claims Commissioner shall be in writing and shall be signed by him.

(3) An order made by the Claims Commissioner shall be executed as a decree of civil court and the provisions of the code of Civil procedure, 1908, so far may be, shall apply as they apply in respect of decree of a civil court.

15. Review of decision.—(1) Any person considering himself aggrieved by any order of the Claims Commissioner, on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain review of such order, may apply for review of a final order not being an interlocutory order, to the Claims Commissioner.

(2) Where it appears to the Claims Commissioner that there is no sufficient ground for a review, he shall reject the application.

(3) Where the Claims Commissioner is of the opinion that the application for review should be granted, he shall grant the same:
Provided that no such application shall be granted without previous notice to the Metro Railway Administration or to enable it to appear and be heard in support of the order, a review of which is applied for.

16. Orders or directions by the Claims Commissioner.—The Claims Commissioner may pass such orders or give such directions as may be necessary or expedient to give effect to his orders or to prevent abuse of the process or to secure the ends of justice.

17. Inherent powers of the Claims Commissioner.—Nothing in these rules shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Claims Commissioner to make such orders as may be necessary for the ends of justice or to prevent abuse of the process of the office of the Claims Commissioner.

18. Association of experts.—(1) The Claims Commissioner may, for the purpose of determining any claim for compensation choose one or more experts possessing any knowledge of any matter relevant to the inquiry.

(2) Compensation, if any, to be paid to the persons associated with the inquiry, as per sub-rule (1) shall be determined by the Claims Commissioner and paid by Metro Railway Administration.

19. Amount of compensation.—(1) The amount of compensation payable in respect of death or injuries, shall be as specified in the Schedule.

(2) The amount of compensation payable for an injury not specified in Part II or Part III of the Schedule but which, in the opinion of the Claims Commissioner, is such as to deprive a person of all his capacity to do any kind of work shall be Rs. 4 lakh (four lakh rupees).

(3) The amount of compensation payable in respect of any injury (other than an injury specified in the Schedule or referred to in sub-rule (2) resulting in pain and suffering, shall be such as the Claims Commissioner may, after taking into consideration medical evidence, besides other circumstances of the case, determine to be reasonable:

Provided that if more than one injury is caused by the same accident, compensation shall be payable in respect of each such injury:

Provided further that the total compensation in respect of all such injuries shall not exceed Rs. 80,000 (eighty thousand rupees).

(4) Where compensation has been paid for any injury which is less than the amount which would have been payable as compensation if the injured person has died or the person subsequently dies of the injury, a further compensation equal to difference between the amount payable for death or amount already paid, shall become payable.

(5) Compensation for loss, destruction or deterioration of goods being carried by the passenger as his personal baggage, shall be paid to such an extent as the Claims Commissioner may, in all circumstances of the case, determine to be reasonable.

20. Limit of compensation.—Notwithstanding anything contained in rule 19, the total compensation payable under that rule shall in no case exceed Rs. 4 lakh (four lakh rupees) in respect of any one person.

SCHEDULE
(See Rule 19)

COMPENSATION PAYABLE FOR DEATH AND INJURIES

PART I

<table>
<thead>
<tr>
<th>For death</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Amount of compensation</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>(in Rs.)</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>4,00,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

PART II

| (1) For loss of both hands or amputation at higher sites | 4,00,000 |
| (2) For loss of hand and a foot | 4,00,000 |
| (3) For double amputation through leg or thigh or amputation though leg or thigh on one side and loss of other foot | 4,00,000 |
| (4) For loss of sight to such an extent as to render the claimant unable to perform any work for which eye sight is essential | 4,00,000 |
| (5) For very severe facial disfigurement | 4,00,000 |
| (6) For absolute deafness | 4,00,000 |
## Part III

<table>
<thead>
<tr>
<th>Description</th>
<th>Amount of Compensation (in Rs.)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) For amputation through shoulder joint</td>
<td>3,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) For amputation below shoulder with stump less than 8&quot; from tip of acromion</td>
<td>3,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) For amputation from 8&quot; from tip of acromion to less than 4½&quot; below tip of olecranon</td>
<td>2,80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) For loss of a hand or the thumb and four fingers of one hand or amputation from 4½&quot; below space tip of olecranon</td>
<td>2,40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) For loss of thumb</td>
<td>1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(6) For loss of thumb and its metacarpal bone</td>
<td>1,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(7) For loss of four fingers of one hand</td>
<td>2,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(8) For loss of three fingers of one hand</td>
<td>1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(9) For loss of two fingers of one hand</td>
<td>80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(10) For loss of terminal phalanx of thumb</td>
<td>80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(11) For amputation of both feet resulting in end-bearing stumps</td>
<td>3,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(12) For amputation through both feet proximal to the metatarsophalangeal joint</td>
<td>3,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(13) For loss of all toes of both feet through the metatarsophalangeal joint</td>
<td>1,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(14) For loss of all toes of both feet proximal to the proximal interphalangeal joint</td>
<td>1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(15) For loss of all toes of both feet distal to the proximal interphalangeal joint</td>
<td>80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(16) For amputation at hip</td>
<td>3,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(17) For amputation below hip with stump not exceeding 5&quot; in length measured from tip of great trochanter but not beyond middle thigh</td>
<td>3,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(18) For amputation below hip with stump exceeding 5&quot; in length measured from tip of great trochanter but not beyond middle thigh</td>
<td>2,80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(19) For amputation below middle thigh to 3½&quot; below knee</td>
<td>2,40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(20) For amputation below knee with stump exceeding 3½&quot; but not exceeding 5&quot;</td>
<td>2,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(21) Fracture of Spine with paraplegia</td>
<td>2,00,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(22) For amputation below knee with stump exceeding 5&quot;</td>
<td>1,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(23) For loss of one eye without complications the other being normal</td>
<td>1,60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(24) For amputation of one foot resulting in end-bearing</td>
<td>1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(25) For amputation through one foot proximal to the metatarsophalangeal joint</td>
<td>1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(26) Fracture of Spine without paraplegia</td>
<td>1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(27) For loss of vision of one eye without complication of disfigurement of eye ball, the other being normal</td>
<td>1,20,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(28) For loss of all toes of one foot through the metatarsophalangeal joint</td>
<td>80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(29) Fracture of Hip-joint</td>
<td>80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(30) Fracture of Major Bone—Femur, Tibia of both limbs</td>
<td>80,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(31) Fracture of Major Bone—Humerus, Radius of both limbs</td>
<td>60,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(32) Fracture of Pelvis not involving joint</td>
<td>40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(33) Fracture of Major Bone—Femur, Tibia of one limb</td>
<td>40,000</td>
</tr>
<tr>
<td>(34) Fracture of Major Bone—Humerus, Radius and Ulna of one limb</td>
<td>32,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

---

**FORM**

(See Rule 3)

Application under Section 58 of the Delhi Metro Railway (Operation and Maintenance) Act, 2002 for claims for compensation in respect of death or injury of passengers or destruction or damage to the goods being carried by them as their personal baggage.
### PART I

Time of the Case:

### PART II

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Description of documents attached</th>
<th>Page No.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

For use in Claims Commissioner's Office

Date of filing
Or
Date of Receipt by post
Registration No.

### PART III

In the Office of the Claims Commissioner

Between

Applicant

and

Metro Railway Administration

1. Particulars of the applicant:
   - Name and address

2. Value of claim—

3. (i) Facts of the case:
   - Give here a concise statement of facts in chronological order, each paragraph containing, as nearly as possible, a separate issue, fact or otherwise
   - (a) Nature of relief sought
   - (b) Ground of relief

4. (i) Matters not previously filed or pending with any other Court,
   - (State whether the applicant had previously filed any claim, writ petition or suit regarding the matter in respect of which the present application has been made)
   - (ii) In case the applicant had previously filed any claims, application, writ petition of suit, indicate the stage at which it is pending, and if decided, attached a certified copy of the order.

5. List of enclosures.

1. 

2. 

3. 

4. 

### Verification

(Name of the applicant) S/o, D/o, W/o....................................................

Age.......................... resident of .................................................

I, __________________________, do hereby verify that the contents of paragraphs to are true to my personal knowledge, and paragraphs to are believed to be true to the best of knowledge, or the legal advice given to me, and that I have not suppressed any material fact.

Date: 
Place: 

Signature of the Applicant

[Signature]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT
(METRO RAIL CELL)

ERRATA

New Delhi, the 1st May, 2007


No. G.S.R. 236(E), New Delhi, the 19th March, 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Reference Page No. and Para No.</th>
<th>For</th>
<th>Read as</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Page No. 6, Para No. 4(6), Line No. 19</td>
<td>may specified</td>
<td>may be specified</td>
</tr>
</tbody>
</table>


S. K. LOHIA, Director (Urban Transport)

| सं.का.नि. 327(अ).—भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय की अधिसूचना सं. सं.का.नि. 237(अ), तारीख 19 मार्च, 2007 जो भारत के राजस्थान, अरसाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) के पृष्ठ 1 से 5 पर प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित के स्थान पर निन नई दिल्ली, 1 मई, 2007 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्रम सं.</th>
<th>पृष्ठ सं.</th>
<th>और पृष्ठ के स्थान पर</th>
<th>पढ़ें</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>पृष्ठ 7, मर्यादा नाम और प्रारंभ मे</td>
<td>खिलाड़ी नेटेक्सेस रेल दाखिला भाषा</td>
<td>खिलाड़ी नेटेक्सेस रेल (दाखिला भाषा)</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>पृष्ठ 8, पृष्ठ 20 और पृष्ठ 28</td>
<td>आवस्थान विचार</td>
<td>आवस्थान अवस्था तथ्य</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>पृष्ठ 8, पृष्ठ 28</td>
<td>प्रतिनिधित्व ने</td>
<td>प्रतिनिधित्व को</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>पृष्ठ 8, पृष्ठ 18</td>
<td>कहाँ</td>
<td>कहाँ</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>पृष्ठ 10, पृष्ठ 37 अनुप्रयोग मे</td>
<td>प्रवासी भर्ती—अधिक संख्या से दोनों पार्थों</td>
<td>प्रवासी भर्ती—अधिक संख्या से दोनों पार्थों के निर्णय से दोनों पार्थों के विद्वेष्टन के लिए</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>पार्थों के</td>
<td>की सब अंगूठियों की हानि के लिए</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

[सं. के-14011/52/2003-एएटी.एस.एसेट्रेक्ट/एस. औ. लोहिया, निदेशक (शहरी वाणि)]
ERRATA

New Delhi, the 1st May, 2007

G.S.R. 327(E).—Ministry of Urban Development's Notification for the Delhi Metro Railway (Procedure to be followed by the Claims Commissioner and amount of compensation payable in case of death and injuries due to accidents) Rules, 2007.

No. G.S.R. 237(E), New Delhi, the 19th March, 2007

<table>
<thead>
<tr>
<th>Sl. No.</th>
<th>Reference Page No. and Para No.</th>
<th>For</th>
<th>Read as</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Page No. 13, Para No. 3(1), Line No. 18</td>
<td>hiduly</td>
<td>his duly</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Page No. 13, Para No. 4(1), Line No. 23</td>
<td>hall</td>
<td>shall</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Page No. 13, Para No. 4(4), Line No. 30</td>
<td>recorded in writing, Decline</td>
<td>recorded in writing, decline</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Page No. 14, Para No. 10(2), Line No. 17</td>
<td>appoint the day the proceeding</td>
<td>appoint the day for proceeding</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Page No. 14, Para No. 11(d), Line No. 25</td>
<td>requisitioning and public record</td>
<td>requisitioning any public record</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Page No. 14, Para 12(1), Line No. 33</td>
<td>unless the considers</td>
<td>unless he considers</td>
</tr>
</tbody>
</table>


S. K. LOHIA, Director (Urban Transport)